ऑस्ट्रेलिया में दस लाख घर बनाएगा भारत

परियोजना का मूल्य करीब 500 अरब डॉलर

ऑस्ट्रेलिया में आवास संकट बना चुनावी मुद्दा

यूएई से मांगी गई वित्तीय सहायता : गोयल

मुंबई, 31 अगस्त.केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है, जिसके तहत भारत ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख घर बनाने के लिए बातचीत कर रहा है. इस विशाल परियोजना को 500 अरब डॉलर का एक बड़ा अवसर बताते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि इसके वित्तपोषण के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से मदद मांगी गई है.

घरेलू उद्योग समूह सीआईआई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने समकक्ष के साथ 10 लाख घर बनाने के लिए बातचीत कर रहा हूँ... यह कम से कम 500 अरब डॉलर का मौका है.

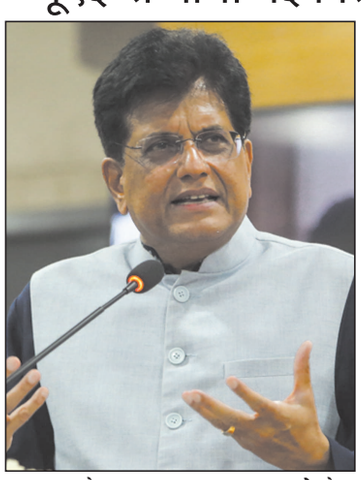

उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के तहत भारतीय कामगारों को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें स्थानीय नियमों के अनुसार घर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया में घरों की मांग और आपूर्ति के बीच बड़े अंतर के कारण वहाँ आवास की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, और हाल के चुनावों में भी यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है. इसी पृष्ठभूमि में, गोयल ने यूएई के वाणिज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जेयोदी के नेतृत्व में आए एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के सामने इस साझेदारी का प्रस्ताव रखा. यूएई भारतीय रियल एस्टेट में एक महत्वपूर्ण निवेशक है, और भारत इस परियोजना के लिए उनकी वित्तीय मदद की उम्मीद कर रहा है.

> व्यापारिक वार्ताओं के मोर्चे पर हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए गोयल ने बताया कि उनका लक्ष्य अगले दो हफ्तों में ओमान के साथ एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर हस्ताक्षर करना है. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ समझौता दो महीनों में और वर्ष के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ भी समझौता होने की संभावना है.

गोयल ने कहा कि आज दुनिया भर के देश विभिन्न प्रकार के गठजोड़ के लिए भारत की ओर देख रहे हैं और हमें ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने कहा, इन अवसरों का लाभ उठाना हमारा काम है. अगर हम चूक गए तो इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होंगे.

बासमती चावल पर से हटेगा प्रतिबंध

किसानों और निर्यातकों को होगा सीधा लाभ

उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद

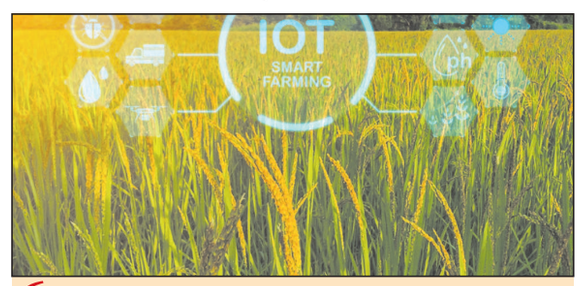

नई दिल्ली, 31 अगस्त. भारतीय चावल निर्यातकों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले महीने फिलीपींस का दौरा करेगा, क्योंकि फिलीपींस ने भारत से खाद्यान्न आयात नियमों में ढील देने का फैसला किया है. इस कदम का मकसद भारत से होने वाले निर्यात को बढ़ावा देना है.

फिलीपींस बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमत हो गया है, जिससे भारत से उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने और भारतीय किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है.हाल ही में फिलीपींस का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, जिसने भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और भारतीय चावल निर्यातक संघ के अधिकारियों से मुलाकात की.

इस मुलाकात के दौरान, फिलीपींस ने चावल के अलावा भैंस का मांस, सब्जियां, फल और मूंगफली जैसे कई खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की. इस समझौते से फिलीपींस को अपनी खाद्य आपूर्ति को अलग-अलग देशों से पूरा करने में मदद मिलेगी.

> फिलीपींस का लक्ष्य अपनी खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और भारत-फिलीपींस के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है . द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के प्रयासों के तहत, फिलीपींस के खाद्य आयातक भारत में होने वाले सबसे बड़े खाद्य व्यापार मेले वर्ल्ड फ़ूड इंडिया और अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन में भी भाग लेंगे .

जियो के बाढ़ प्रभावितों को राहत

मुफ़्त वैधता विस्तार और अतिरिक्त सुविधाएँ

नई दिल्ली, 31 अगस्त. हाल ही में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और बाढ़ से प्रभावित जियो ग्राहकों के लिए कंपनी ने विशेष राहत उपायों की घोषणा की है. कंपनी का उद्देश्य इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आवश्यक संचार सेवाओं और कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना है.

जियो ने प्रभावित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं

प्रीपेड और जियोहोम ग्राहकों के लिए जिन ग्राहकों के प्लान इस सप्ताह समाप्त हो रहे हैं, उनकी वैधता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा. इन ग्राहकों को असीमित वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 2जीबी हाई-स्पीड डेटा भी उपलब्ध रहेगा.

वाटर प्यूरिफायर, फिल्टर को पांच प्रतिशत के स्लैब में लाने की मांग

नयी दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक से पहले वाटर प्यूरिफायर, फिल्टर और इनसे संबंधित सेवाओं को पांच प्रतिशत के स्लैब में लाने की मांग की गयी है. वाटर प्यूरिफायर और फिल्टर बनाने वाली कंपनियों, इनके डीलरों और कलपुर्जों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के अलाभकारी संगठन वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने इस संबंध में केंद्रीय राजस्व सचिव को एक पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि स्वच्छ पेय जल तक पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है. केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, देश के कई हिस्सों में भूजल पीने लायक नहीं है और इसलिए लोग मजबूरी में वाटर प्यूरिफायर और फिल्टर इस्तेमाल करते हैं.

गेहूं, खाद्य तेल महंगे ; चावल, दाल और चीनी सस्ती

53 रु. की तेजी आई मूंगफली में

14 रु. गेहूं और आटा 4 रुपये महंगा

नयी दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता)- बीते सप्ताह घरेलू थोक जिंस बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया. चावल के औसत भाव तीन रुपये प्रति क्विंटल गिर गए, जबकि गेहूं करीब 14 रुपये और आटा चार रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया.

खाद्य तेलों में भी उतार-चढ़ाव रहा. मूंगफली तेल में सबसे अधिक करीब 53 रुपये की तेजी आई, जबकि सरसों, वनस्पति, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के दाम भी बढ़ गए. हालांकि, पाम ऑयल 11 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया.

दालों के बाजार में नरमी देखी गई. चना, उड़द, मूंग और तुअर दाल के भाव में गिरावट आई, जबकि मसूर दाल की कीमत कमोबेश स्थिर रही. मीठे के बाजार में गुड़ और चीनी की कीमतों में भी गिरावट आई, जिससे हाल में चल रही तेजी पर ब्रेक लग गया.

सरकारी वेबसाइट पर खाद्यान्नों के थोक भाव

दाल-दलहन-दाल चना- 7961.07 रुपये/क्विंटल, मसूर काली 8109.48 रुपये/क्विंटल, मूंग दाल- 10103.51 रुपये/क्विंटल, उड़द दाल- 10434.10 रुपये/क्विंटल, अरहर दाल- 10672.95 रुपये/क्विंटल **अनाज**-गेहूं दड़ा- 2855.55 रुपये/क्विंटल, चावल- 3827.63 रुपये/क्विंटल, **चीनी-गुड़**-चीनी एस- 4309.18 रुपये/क्विंटल गुड़- 4945.55 रुपये/क्विंटल

खाद्य तेल-

- सरसों तेल- 17858.53 रुपये/क्विंटल
- मूंगफली तेल- 17674.79 रुपये/क्विंटल
- सूरजमुखी तेल- 15424.97 रुपये/क्विंटल
- सोया रिफाइंड- 13879.98 रुपये/क्विंटल
- पाम ऑयल- 12359.41 रुपये/क्विंटल

चीन के निर्यात प्रतिबंध से भारत में उर्वरक आपूर्ति पर असर

नई दिल्ली, 31 अगस्त. चीन द्वारा अक्टूबर से विशेष उर्वरकों पर निर्यात प्रतिबंध फिर से लगाने की आशंका है, जिससे भारत के उर्वरक उद्योग को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ (एसएफआईए) के अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती के अनुसार, चीन निर्यात को पूरी तरह से नहीं रोकेगा, बल्कि निरीक्षण और देरी करके इसे सीमित करेगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं. हालाँकि, भारत ने सात वर्षों के अनुसंधान के बाद अपनी पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित कर ली है, जो आयात पर निर्भरता कम करने में सहायक हो

डिजिलॉकर से जुड़ीं 2,000 डिजिटल सेवाएं

36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कहीं भी, कभी भी उपलब्ध होंगी ई-सेवाएं

नई दिल्ली, 31 अगस्त. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस एकीकरण से, अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक लगभग 2,000 डिजिटल सेवाओं का लाभ कभी भी, कहीं भी उठा सकेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये सेवाएं प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाओं, सुविधा केंद्र भुगतानों और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित नागरिकों की व्यापक जरूरतों को पूरा करती हैं. यह प्रगति डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कागज रहित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देता है.

डिजिलॉकर अपनी डेटा सुरक्षा और मजबूत ढांचे के कारण भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है. इसने देश भर के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ, समावेशी और विश्वसनीय बनाया है.

> इस विस्तार के बाद, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 254 सेवाएं उपलब्ध हैं . इसके बाद दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएं उपलब्ध हैं . केरल और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक 77 सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश 76 और गुजरात 64 सेवाएं प्रदान करता है . एनईजीडी ने इस सफलता के आधार पर, ई-सरकारी सेवाओं के पोर्टफोलियो को और विस्तारित करने की योजना बनाई है .

एक सप्ताह में रुपया 0 .65 प्रतिशत टूटा, ऐतिहासिक निचले स्तर पर

मुंबई, 31 अगस्त (वार्ता) विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय पूंजी बाजार में बिकवाली और घरेलू शेयर बाजारों में रही गिरावट के दबाव में रुपया बीते सप्ताह 56.50 पैसे शुक्रवार को अंतिम कारोबारी दिवस पर 88.09 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. भारतीय मुद्रा पहली बार 88 रुपये प्रति डॉलर से नीचे बंद हुई है. इससे पहले इसका निचला स्तर 87.88 रुपये प्रति डॉलर था. विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी बाजार में भारी बिकवाली से डॉलर की मांग बढ़ी है.

सेंसेक्स-निफ्टी साप्ताहिक रूप से गिरे

सेंसेक्स 1,497 अंक लुढ़ककर 79,809 .65 पर

मुंबई, 31 अगस्त (वार्ता)- बीते सप्ताह शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, अब निवेशकों की नजरें अगले सप्ताह पर टिकी हैं, जहां उत्साहजनक जीडीपी आंकड़ों का असर दिख सकता है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.8 प्रतिशत रही, जिसका असर बाजार खुलने पर दिखेगा.

पिछले सप्ताह बाजार में बिकवाली हावी रही. बीएसई का

सेंसेक्स 1,497.20 अंक यानी 1.84 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट के साथ 79,809.65 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 443.25 अंक (1.78 फीसदी) टूटकर 24,426.85 अंक पर आ गया. मझौली और छोटी कंपनियों में बिकवाली और भी अधिक रही, जहां निफ्टी मिडकैप50 और निफ्टी स्मॉलकैप-100 सूचकांक क्रमशः 3.63 प्रतिशत और 3.86 प्रतिशत टूट गए.

सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियों के शेयर लुढ़क गए, जिनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा (6.01%), रिलायंस इंडस्ट्रीज (3.71%) और एचडीएफसी बैंक (3.15%) शामिल हैं.

समाचार विशेष

न मांग पूरी करना आसान न करने देंगे प्रस्थान

मोदी और एनडीए के लिए 'गुड़ भरी हंसिया' बने चिराग पासवान!

पटना. बिहार में चुनावी महाभारत का अनौपचारिक शंखनाद हो चुका है. एक तरफ नीतीश कुमार रोजाना नई घोषणाएं कर कुर्सी पर पकड़ बनाए रखने की कवायद में जुटे हुए हैं, दो दूसरी तरफ पीएण मोदी सूबे को विकास के सौगात देकर एनडीए के पक्ष में सियासी माहौल बना रहे हैं. लेकिन इस सब के इतर 'मोदी के हनुमान' की सियासी मांग एनडीए के लिए चिंता का सबब बन गई है.

चिराग पासवान की डिमांड के कारण ही बीजेपी और जेडीयू के खेमें में अंधेरा छाया हुआ है. लेकिन पासवान के साथ-साथ दलित और अति पिछड़े वोटर्स- जिनमें चिराग की पैठ अच्छी खासी है, उनको अपने पाले में बनाए रखने के लिहाज से भी एनडीए के लिए बिहार में चिराग का साथ जरूरी है. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में भाजपा, चिराग पासवान की लोजपा (आर), जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं. इस प्रकार, एनडीए गठबंधन का स्वरूप तो तय हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है. सूत्रों की मानें तो भाजपा और जदयू बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग करके राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है. चिराग की मांग के अनुसार सीटें देना असंभव सा लग रहा है. ऐसे में उनके खाते में 20 से 25 सीटें ही आ सकती हैं, क्योंकि भाजपा-जदयू को मांझी और कुशवाहा को सीटें देनी हैं.

क्या पूरी हो पाएगी चिराग की डिमांड?- चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 40 सीटों की मांग की है, जो पूरी नहीं हो सकती. ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें ही मिल सकती हैं.

> **कैसा होगा एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला?**
>
> बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से अगर भाजपा और जदयू बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, तो उन्हें 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं . इस लिहाज से दोनों दलों के बीच 200 से 210 सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि भाजपा और जदयू दोनों ही किसी भी हालत में 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे . इसकी वजह यह है कि 2020 में जदयू ने 115 और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था . इस लिहाज से अगर भाजपा और जदयू पिछले चुनाव से कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत होते हैं, तो एनडीए के बाकी तीन घटक दलों के बीच 33 से 43 सीटें बंट जाएंगी .

बसपा की दमदार वापसी का 9 अक्टूबर प्लान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी की कोशिश के प्रयास में है. दो दशक के बाद एक बार फिर मायावती बदली रणनीति के साथ यूपी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. बसपा प्रमुख मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है. लगातार कमजोर हो रहे जनाधार और चुनावी हारों के बीच मायावती अब 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी हैं.

इसी सिलसिले में उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को 'मिशन-2027' की औपचारिक शुरुआत करने का फैसला लिया है. मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है. साथ ही, पिछले दिनों विवादित मसलों पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकारों को घेरा है, उससे साफ है कि वे विवादों से बच रही हैं. ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव लेने का है. अगर मायावती की रणनीति सफल होती है तो यह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होगी.

9 अक्टूबर से जुटेंगे कार्यकर्ता

मायावती की प्लानिंग पूरे प्रदेश में एक बार फिर बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की है. कोविड काल के बाद से मायावती काफी कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखी हैं. यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनकी जनसभाओं की संख्या उस स्तर की नहीं रही, जैसी पहले दिखती थी. चुनावों के समय में मायावती खुद को एक्टिव कर लगभग हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करती थीं

विशेष | **प्रशांत किशोर ने एक्टिव किया लालू के एमवाय में सेंधमारी का प्लान**

बिहार चुनाव में कैसे बढ़त बनाएगी जन सुराज?

मोतिहारी. बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीनों का वक्त बचा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट हुए हैं. इधर बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर भी एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

पीके ने लालू यादव के एमवाय (मुस्लिम-यादव) समीकरण में सेंधमारी के लिए अपना प्लान एक्टिव कर दिया है. प्रशांत किशोर ने बीते दिन मोतिहारी के बापू सभागार में

मुस्लिम एकता सम्मेलन आयोजित कर राजद के परंपरागत एमवाय समीकरण को चुनौती दी. इस सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में भागीदारी रही और कई लोगों ने खुले तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की यह पहल बिहार की राजनीति को बदल सकती है.

प्रशांत किशोर ने सम्मेलन में भावनात्मक अपील की. उन्होंने कहा, हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए. आपके साथ के लिए हम इंतजार कर रहे हैं. उनका संदेश साफ था- वे सिर्फ चुनावी वोट बैंक नहीं, बल्कि स्थायी समर्थन और सहभागिता चाहते हैं.

> **पारंपरिक राजनीति से अलग राह**
>
> राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर पारंपरिक राजनीति से अलग एक नया जनाधार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं . जन सुराज अभियान के जरिए वे सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और उन्हें राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं . उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति बनाना है . अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर सचमुच लालू यादव के एमवाय समीकरण को तोड़ पाएंगे ? क्या मुस्लिम समुदाय परंपरागत राजनीति छोड़कर उनके साथ खड़ा होगा ? इन सवालों का जवाब आने वाले चुनावों में मिलेगा . लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है .

तेजस्वी का नाम घोषित करने में राहुल की हिचक

पटना. बताया जा रहा है राजद की ओर से तमाम दबाव के बावजूद कांग्रेस अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने को तैयार नहीं है. एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने यह फैसला किया है. तभी राहुल गांधी ने अररिया में तेजस्वी का नाम नहीं लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा है.

कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने अभी घोषणा टाली है. हालांकि इसे लेकर कांग्रेस में दो बातें कही जा रही हैं. एक बात को यह कही जा रही है कि कांग्रेस पिछली बार जिन 70 सीटों पर लडी उसमें से ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने

पास रखना चाहती है. कांग्रेस को पता है कि इस बार 70 सीटें नहीं मिलेंगी. उसको पता है कि इसमें से कम से कम सीटें छोड़नी पड़ी. इसके लिए मोलभाव का अंतिम हथियार उसके पास मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है. तभी तेजस्वी के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे की टेबल पर उनका नाम घोषित करेगी.

> **जमीन पर तैयारी पर जोर**
>
> मायावती ने इस बार बिना शोर-शराबे के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने का तरीका अपनाया है . उन्होंने कई कमेटियों का गठन कर गांव-गांव बैठकों और छोटी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी है . पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बनाना चाहती है . दरअसल, इस समय भाजपा और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं . ऐसे में बसपा जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई है .